Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): There is lathi charge and firing outside. I have also received lathi blow. You cannot go on like this.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सभा का कार्य नहीं चल सकता है। श्री कछवाय कृपा करके बाहर चले जायें आखिर सभा में तो शांति रखी ही जानी चाहिए।

(इसके पश्चात् श्री कछवाय सभा से बाहर चल गये)
(**Shri Kachhavaiya then left the House.**)

श्री राजाराम (कृष्णागिरि): मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 1962 में हमने कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए आन्दोलन किया था। हमने इस बारे में जो सलाह दी थी सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकार करदाताओं के माल को बहुत बुरी तरह खर्च करती रही है और मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही शोचनीय बना दी गई है। इसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, परन्तु सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया और कीमतें निरन्तर बढ़ती चली गयीं। अब बिना किसी विचार के रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया और अब सरकार स्वयं ही खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ा रही है। मेरा मत यह है कि यदि सरकार को हमनें इसी तरह छूट दिये रखी तो शीघ्र ही देश में बड़ी भयंकर स्थिति का निर्माण हो जायेगा। सरकार को कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए तुरन्त पग उठाने ही होंगे। यह भी कहा गया है कि हम 800 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। चाय, पटसन और रूई की चीजें लगभग 400 करोड़ रुपये की निर्यात की जाती हैं। अब हमारा निर्यात व्यापार भी खतरे में है। इस बारे में स्थिति यह है कि जब रुपये का अवमूल्यन हुआ था तो उस समय यह कहा गया था कि इस तरह हम और अधिक विदेशी मुद्रा कमा लेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा निर्यात संकट में है। इस तरह यह आशा करना भी गलत होगा कि लोग सरकार पर विश्वास रखते हैं।

मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि सेलम के लिए कई वर्षों से एक इस्पात के कारखाने की मांग की जा रही है परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में केवल एक अस्पष्ट आश्वासन देने के अतिरिक्त कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। आश्चर्य की बात है कि संयन्त्र के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तो तैयार रखा है परन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। बोकारो कारखाने के लिए सरकार 900 करोड़ रुपये देने को तैयार है परन्तु दक्षिण में एक संयन्त्र लगाने के लिए सरकार केवल 300 करोड़ भी व्यय नहीं करना चाहती। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दक्षिण के विरुद्ध कोई षड्यन्त्र चल रहा है।

अब यह नारा लगाया जा रहा है कि 'एक दल, एक झंडा और एक नेता'। मैं अपने विशिष्ट बन्धुओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए बलिदान किये थे कि हम इस देश में तानाशाही की स्थापना करें। मेरा विचार यह है कि यदि यह नारा सफल हो गया तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। योजना भी हमारी प्रायः असफल हो रही है। पर इस पर भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सम्मेलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी यह कहती है कि गैर कांग्रेसी सरकार को क्रांति से उखाड़ फैंका जायेगा। क्या ऐसा लोकतंत्र संसार भर में हमने कभी देखा है। शक्ति और गोली के बल से ये लोग अपनी सत्ता कायम रखेंगे। (अंतर्बाधा) **

प्रधान मंत्री और अन्य शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस विवाद के दौरान कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो पहले कभी न सुनी गयी हो अथवा न कही गई हो। यद्यपि विरोधी पक्ष की अलग अलग राय हैं परन्तु फिर उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त

कार्यवाही से निकाल दिया गया।

680 Not recorded.

करने का अवसर दिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। आज जो हिंसा का वातावरण बना हुआ है, उस पर मुझे बहुत ही क्षोभ है। जो कुछ बाहर हो रहा है, वह आपके सामने है। चाहे यह विद्यार्थी लोग कर रहे हों, अथवा अन्य लोग। मैं यह महसूस करती हूं कि हिंसा को जान बूझ कर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में हिंसात्मक कार्य किये जायें और हम शक्ति का प्रयोग करें। परन्तु क्या किया जाय जब सरकारी इमारतों को जलाया जाय और विविध प्रकार से कानून तोड़ा जाय तो फिर क्या किया जाये। शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है।

आज देश की स्थिति ऐसी नहीं कि हम छोटी-छोटी चीजों के लिए लड़ते रहें। छोटे-छोटे दलगत मामलों पर उलझते रहें। आज तो हमें राष्ट्र के हित में कदम मिला कर चलना होगा। जो शिकायतें हैं उन्हें सुनने से हमें कभी आपत्ति नहीं हुई। यदि शिकायतों को ठीक तरह से प्रस्तुत किया जाय तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। मेरा मत यह है कि राज्यों को शिकायतों को प्रकट करने के ढंग का विरोध जरूरी करना होगा, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते, तो अन्य साधन अपनाने पड़ेंगे। वह तरीका और भी अधिक खतरनाक होगा और उसके लिए कहीं अधिक कीमत चुकानी होगी। इस बारे में दुःख की बात यह है कि विद्यार्थी भी यह नहीं जानते कि उनकी मांग क्या है।

जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जो कुछ बाहर हो रहा है यह सरकार पर ही आक्रमण नहीं है। यह तो हमारी जीवन पद्धति, मान्यताओं और विचारधारा को समाप्त करने का भी प्रयास है। हम अपने विचारों पर दृढ़ है। हमारा अहिंसा के सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास है चाहे कोई इसका उपहास ही क्यों न करे। हमनें क्योंकि अहिंसा के रास्ते को ही ठीक समझा इसलिए दृढ़ता से उस पर चलते रहे। उसमें हमें सफलता भी मिली है। फिर यह भी बात है कि हमनें इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। हम भी विरोधी पक्ष को पूरी प्रतिष्ठा देने को तैयार हैं, परन्तु मेरा निवेदन है कि कई बार विरोधी दलों के सदस्य अवसरों का अनुचित लाभ उठाते है, और आज जो कुछ बाहर हुआ है, यह इसका एक उदाहरण है। आज जो कुछ किया जा रहा है यह लोकतंत्र को समाप्त करने वाली बातें हैं। मेरा पक्का विचार है कि यदि सरकार स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला नहीं करती है, तो लोकतंत्र नहीं चल सकता।

देश के समक्ष बहुत कठिनाइयां हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेटों को बहुत कठिन परीक्षा से निकलना पड़ रहा है। यदि वे तुरन्त कुछ नहीं करते तब भी शिकायतें होती है और यदि वह कड़ी कार्यवाही करते है तो तब भी कोलाहल होने लगता है। ठीक है यदि शक्ति का प्रयोग होगा तो कई मासूम व्यक्तियों को भी हानि उठानी होगी। मुझे इसका दुःख है और ऐसे लोगों से मुझे पूरी सहानुभूति है और उनकी सहायता भी करनी चाहिए। परन्तु स्थिति का मुकाबला तो मजबूती से करना ही होता है। जो भी कठिनाइयां हैं, मेरा मत यह है कि हमें स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक होना चाहिए और सामूहिक प्रयत्न करने चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि देश के कुछ भागों में सूखे की भयंकर स्थिति है और आज यह संकट बड़े गम्भीर रूप में हमारे सामने हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बड़े प्रयत्न कर रही हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने

[श्री राजा राम]

एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है जो सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों में सहयोग प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमें हर स्तर पर तेजी से कार्य करना है तथा जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई उन क्षेत्रों में अनाज इत्यादि भेजा जाय। हमें ऐसा भी करना होगा कि जो कुछ हमारे पास है उसका ठीक तरह से वितरण हो जाय। हमें इस तरह के आन्दोलनों की व्यवस्था करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों को अपेक्षित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुयें दी जा सकें।

मेरा अब भी यह मत है कि स्थिति जैसी भी हो पर उसे ठोस कदम जठा कर बदला जा सकता है। उत्पादन के लिए स्थायी साधन निर्माण किये जा सकते हैं। सहायता कार्य को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कृषि उत्पादन बढ़े और वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके। निर्माण कार्य को भी काफी प्लाभदायक ढंग से संगठित करना होगा। इसे बढ़ाना भी होगा। मुझे आशा है कि बच्चों के अन्नपोषण के कार्य को भी शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें वास्तव में गरीबी से लड़ना है। खाद्य समस्या भी इस गरीबी की समस्या का एक अंग है। हम अपनी योजनाओं के माध्यम से उसका सामना कर रहे है। हो सकता है कि मैं अपनी चौथी योजना के लिए पर्याप्त सहायता न मिले, फिर भी हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिएं।

इस बात को भी समुचित रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए कि जहां तक इस्पात संयन्त्रों तथा अन्य उद्योगों के स्थानों का सम्बन्ध है हम सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखना चाहते हैं परन्तु इस समय हमें सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इस समय इस्पात संयन्त्रों की बात करना बहुत ही अव्यवहारिक बात है। अभी तुरन्त उन्हें स्थापित कर देने का तो प्रश्न ही नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम जनता की भावनाओं को ठुकरा रहे हैं। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भूख हड़तालें और प्रदर्शन करके सरकार को कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और न सरकार होगी ही।

बहुत से माननीय सदस्यों ने विदेश नीति पर आलोचना की है। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष तौर पर उल्लेख किया है। मेरा निवेदन यह है कि हमें इस सम्मेलन का उपहास नहीं करना चाहिए। सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, यद्यपि उसका निश्चित परिणाम कुछ समय बाद सामने आयेगा। जहां तक इस अविश्वास प्रस्ताव का का सम्बन्ध है इसके लिए अवास्तविक वातावरण पाया जाता है। थोड़ी ही समय में हमारी परीक्षा होने वाली है। हमें जनता की राय जानने के लिए उसके सामने जाना है। मुझे इस बात का विश्वास है कि अन्तिम विजय हमारी होगी, लोग हमें पुनः अपना विश्वास प्रदान करेंगे। यद्यपि समय बड़ा कठिन है तथापि हमें लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तो बनाये ही रखनी है।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): I have gone out of the House but my faith in democracy has urged me to come back. We are sitting here, but outside, there is firing going on. If we allow such thing to happen in a democratic set up, then the future of democracy is very dark. Only a Judicial probe can tell us, who is at fault. But Government will have to put an enquiry for that. We should try to act up to the standards of democracy and should not lower down our pedestal.